ASSOCHAM IN THE NEWS

Dainik Bhaskar (Udaipur) — **19 April, 2018**

यूसीसीआई की फूड प्रोसेसिंग पर कार्यशाला : उद्योग मंत्री शेखावत बोले- सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने से नहीं होगा

यूके में सालभर में जितना अनाज खपत होता, उतना भारत में हो जाता है बर्बाद, बचाने के लिए स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च हो

यूसीसीआई में कार्यशाला में मौजूद लोग और संबोधित करते मंत्री।

उदयपुर | उद्योग मंत्री राजपालसिंह शेखावत ने कहा है कि यूके में सालभर में जितने खाद्यान्न का उपभोग होता है, उतना भारत में बेकार हो जाता है। इसे बचाने का एक ही रास्ता है कि इस क्षेत्र में स्किल डवलपमेंट और रिसर्च हो। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने से कुछ नहीं होगा, फूड प्रोसेसिंग में रिसर्च और स्किल डवलपमेंट की जरूरत है।

शेखावत बुधवार को उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (यूसीसीआई) के पीपी सिंघल सभागार में खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। यूसीसीआई, एसोचैम, एमपीयूएटी और खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की इस कार्यशाला में शेखावत बोले कि देश में अनाज का इतना उत्पादन होता है कि हर व्यक्ति को तीन समय का भोजन मिल सके। हमारे यहां हर साल करीब 92 हजार करोड़ का खाद्यान्न बरबाद हो जाता है। मंत्री बोले, हमने आईआईएम-यू, आईआईटी जोधपुर तो खोल दिए, लेकिन क्या इन सेंटर्स पर उस स्तर का स्किल डवलप हो रहा है, जिसके लिए ये संस्थान महत्व रखते हैं। इस पर यूसीसीआई अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने बताया कि यूसीसीआई ने यहां मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के साथ स्किल डवलपमेंट सेंटर की स्थापना का एमओयू किया है। इस सेंटर के तहत फूड प्रोसेसिंग, आईटी, सिविल, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में क्षमता विकास के काम होंगे। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पराग गुप्ता ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर केन्द्र सरकार की सात योजनाएं बताईं। कहा कि केन्द्र सरकार की मदद से युवा इस क्षेत्र में इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं। कार्यशाला में यूएस एम्बेसी के डेलीगेट डगलस फलोवर और जैक माइनर, एसोचैम के वरिष्ठ निदेशक डॉ. ओम एस. त्यागी, यूसीसीआई के संरक्षक अरविन्द सिंघल, जिला उद्योग केन्द्र के संयुक्त निदेशक विपुल जानी, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय गुप्ता सहित कई उद्यमी और विशेषज्ञ शामिल हुए।

यह भी बोले मंत्री- खाद्यान्न प्रसंस्करण हमारे डीएनए में

मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न प्रसंस्करण हमारे डीएनए में है। घरों में बनने वाले आलू के चिप्स इसी का हिस्सा हैं। किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए सिर्फ पैदावार बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि खाद्यान्न के प्रसंस्करण पर आधारित उद्योगों की भी स्थापना हो। नाबार्ड उदयपुर के डीडीएम ने नाबार्ड से पोषित परियोजनाओं की जानकारी दी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास एवं क्षमतावर्धन के लिए 2 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत करने की जानकारी दी।

यूसीसीआई ने बताया- इंडस्ट्री के लिए हमारे पास भूमि नहीं है

यूसीसीआई ने उद्योग मंत्री के सामने इंडस्ट्री के लिए भूमि की उपलब्धता नहीं होने की समस्या रखी। अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि सराड़ा को इंडस्ट्रीयल हब बनाने के लिए 10 साल से भूमि अवाप्ति की योजना चल रही थी, लेकिन निरस्त हो गई। कलड़वास में अवाप्ति हो गई, लेकिन इंडस्ट्री को जमीन नहीं मिली। शेखावत ने समाधान का भरोसा दिलाया।

Rajasthan Patrika (Udaipur) 19 April, 2018

देश में सालाना करीब 92 हजार करोड़ का खाद्यान वेस्ट हो जाता -शेखावत

खाद्यान्न के प्रसंस्करण पर आधारित उद्योगों की स्थापना हो

एसोचेम, यूसीसीआई का सम्मेलन

उदयपुर. उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा देश में खाद्यान्न का इतना उत्पादन होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को तीन समय का भोजन आसानी से उपलब्ध हो सके पर देश में प्रति वर्ष करीब 92 हजार करोड़ का खाद्यान्न बेकार हो जाता है, जिससे देश के करोड़ों लोगों को मात्र एक समय ही भोजन उपलब्ध हो पाता है।

यह बात उन्होंने बुधवार को एसोसियेटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एसोचेम) इण्डिया, उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (यूसीसीआई), महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना विषयक सम्मेलन में कही। यहां यूसीसीआई के पी.पी. सिंघल ऑडीटोरियम में हुए सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इसी तथ्य के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है किन्तु मात्र खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने मात्र से किसान की आमदनी दोगुनी नहीं हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि खाद्यान्न के प्रसंस्करण पर आधारित उद्योगों की स्थापना हो। कुछ वर्षों में राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है । शेखावत ने कहा कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की राजस्थान में विपुल संभावनाएं हैं, इससे कृषि में रोजगार सृजन के साथ ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता का भी विकास होगा।

दक्षिण राजस्थान में फूड पार्क की स्थापना हो : यूसीसीआई के अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने क्षेत्र में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना पर जोर देते हुए कहा कि दक्षिण राजस्थान में फूड पार्क की स्थापना के लिए विशेष प्रयास किए जाए। चौधरी ने यूसीसीआई की ओर से उद्योगों की समस्याओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पराग गुप्ता ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने तथा उद्यमियों से इन योजनाओं का लाभ लेने एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने पर जोर दिया।

शंकाओं का समाधान : प्रश्नकाल के दौरान संयुक्त सचिव गुप्ता ने छात्रों एवं उद्यमियों की शंकाओं का समाधान किया। एसोचेम के वरिष्ठ निदेशक डॉ. ओम एस. त्यागी ने एसोचेम द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं इसकी जागरूकता बढ़ाने में एसोचेम के प्रयासों से प्रतिभागियों को अवगत कराया। यूसीसीआई के संरक्षक अरविन्द सिंघल एवं जिला उद्योग केन्द्र के संयुक्त निदेशक विपुल जानी ने भी विचार रखे। तकनीकी सत्र के दौरान ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय गुप्ता ने मेगा फूड पार्क के माध्यम से खाद्यान्न के उचित उपयोग को रेखांकित किया। नाबार्ड-उदयपुर के डीडीएम शशिकमल ने नाबार्ड की ओर से पोषित विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी दी। कृषि उपज मण्डी के भगवान सिंह जटवा ने औषधीय पौधों के उपयोग एवं इन पर आधारित उद्योगों की सम्भावनाओं पर चर्चा की।

Dainik Navjyoti (Udaipur) 19 April, 2018

भारत में बर्बाद होता है 92 हजार करोड़ का खाद्यान्न: शेखावत

खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना पर एसोचेम-यूसीसीआई के साझे में सम्मेलन

उदयपुर। प्रदेश के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि वर्तमान में देश में खाद्यान्न का इतना पैदा होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को तीन समय का भोजन आसानी से उपलब्ध हो सके, किन्तु दुर्भाग्य है कि प्रति वर्ष लगभग 92 हजार करोड़ रुपए मूल्य का खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है। इससे देश के 20 करोड़ लोगों को एक समय ही भोजन सुलभ हो पा रहा है।

उद्योग मंत्री शेखावत ने यह बात बुधवार को एसोसियेटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचेम) इंडिया, उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (यूसीसीआई), महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय व खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में यूसीसीआई सभागार में खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना विषय पर आयोजित सम्मेलन में कही।

आमदनी बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा उत्पादन: उद्योग मंत्री शेखावत ने कहा, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, किन्तु मात्र खाद्यान का उत्पादन बढ़ाने मात्र से किसान की आमदनी दोगुनी नहीं हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि खाद्यान के प्रसंस्करण पर आधारित उद्योगों की स्थापना हो। आधारभूत सुविधाओं का इस्तेमाल स्किल डेवलपमेन्ट द्वारा देश की युवा जनसंख्या को मानव संसाधन में तब्दील करने में होना चाहिए।

उदयपुर आईआईएम को नहीं मिल सकी ख्याति: उद्योग मंत्री ने उदयपुर के आईआईएम और जोधपुर के एम्स को अन्य संस्थानों की भांति ख्याति नहीं मिलने पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि हमें ह्यूमन रिसोर्स पर काम करने की आवश्यकता है।

राजस्थान में हो सकेगा रोजगारों का सृजन

उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के माध्यम से राजस्थान में नए रोजगार के सृजन की संभावनाओं पर प्रकाश डाला एवं संभाग के विभिन्न कृषि उत्पादों पर आधारित कृषि व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों संभावनाओं पर जानकारी दी।

विशिष्ट अतिथि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पराग गुप्ता ने खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने पर जोर दिया। प्रश्नकाल के दौरान गुप्ता ने छात्रों एवं उद्यमियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। एसोचेम के वरिष्ठ निदेशक डॉ. ओम एस. त्यागी, यूसीसीआई के संरक्षक अरविन्द सिंघल एवं जिला उद्योग केन्द्र के संयुक्त निदेशक विपुल जानी ने भी विचार रखे। तकनीकी सत्र के दौरान ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय गुप्ता ने मेगा फूड पार्क के माध्यम से खाद्यान्न के उचित उपयोग को रेखांकित किया। नाबार्ड के डीडीएम शशिकमल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास एवं क्षमतावर्द्धन के लिए 2 हजार करोड़ रुपए स्वीकृति की जानकारी दी। जीवना वाइटेलिटी के पैट्रिक श्वाटर तथा ईव्स सूट्स ने अपने स्टार्ट-अप का परिचय देते हुए उनकी सेवाओं में किए नवाचार के बारे में बताया। कृषि उपज मंडी के भगवान सिंह जटवा ने औषधीय पौधों के उपयोग एवं इन पर आधारित उद्योगों की संभावनाओं पर चर्चा की।

19 April, 2018

Udaipur Express (Udaipur)

ASSOCHAM IN THE NEWS

राजस्थान में खाद्यान्न प्रसंस्करण पर आधारित उद्योग स्थापित हो: उद्योग मंत्री

खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना पर सम्मेलन का आयोजन

उदयपुर। केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट पर्याप्त नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर का समुचित उपयोग आवश्यक है। आधारभूत सुविधाओं का इस्तेमाल स्किल डेवलपमेन्ट द्वारा देश की युवा जनसंख्या को मानव संसाधन में तब्दील करने में होना चाहिये। उपरोक्त विचार उद्योगमंत्री राजपालसिंह शेखावत ने यूसीसीआई में व्यक्त किये।

एसोसियेटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एसोचेम) इण्डिया, उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (यूसीसीआई), महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रधानमंत्री किसान संम्पदा योजना विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन यूसीसीआई के पी.पी. सिंघल ऑडीटोरियम में किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि राज्य सरकार के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि देश में खाद्यान का इतना उत्पादन होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को तीन समय का भोजन आसानी से उपलब्ध हो सके। किन्तु देश में प्रति वर्ष लगभग 92 हजार करोड़ का खाद्यान वेस्ट हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप देश के करोड़ो लोगों का मात्र एक समय ही भोजन उपलब्ध हो पाता है। इसी तथ्य के मद्देनजर केन्द्र सरकार द्वारा सन 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। किन्तु मात्र खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने मात्र से किसान की आमदनी दोगुनी नहीं हो जायेगी। इसके लिये जरूरी है कि खाद्यान के प्रसंस्करण पर आधारित उद्योगों की स्थापना हो। विगत कुछ वर्षों में राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। शेखावत ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे राजस्थान के आर्थिक विकास एवं कृषि का मुख्य आधार स्तम्भ बताया। उन्होंने कहा कि कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की राजस्थान में विपुल संभावनाएं हैं। इससे कृषि में रोजगार सृजन के साथ ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता का भी विकास होगा।

उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष हंसराज चौधरी ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के माध्यम से राजस्थान में नए रोजगार के सृजन की संभावनाओं पर प्रकाश डाला एवं सम्भाग के विभिन्न कृषि उत्पादों पर आधारित कृषि व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो संभावनाओं पर जानकारी दी।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उद्योग मंत्री राजपालसिंह शेखावत

कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पराग गुप्ता ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने तथा उद्यमियों से इन योजनाओं का लाभ लेने एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने पर जोर दिया। इस सम्मेलन में मुख्य रुप से किसानों एवं कृषि एवं खाद्यान प्रसंसकरण उद्योग से जुडे प्रतिभागियों ने महत्वपूर्ण विचारों का आदान-प्रदान किया।

प्रश्नकाल के दौरान संयुक्त सचिव पराग गुप्ता ने छात्रों एवं उद्यमियों के शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस अवसर पर एसोचेम के वरिष्ठ निदेशक डॉ. ओम एस. त्यागी ने एसोचेम द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं इसकी जागरूकता बढ़ाने में एसोचेम के प्रयासों से प्रतिभागियों को अवगत कराया। यूसीसीआई के संरक्षक अरविन्द सिंघल एवं जिला उद्योग केन्द्र के संयुक्त निदेशक विपुल जानी ने भी विचार रखे।

तकनीकी सत्र के दौरान ग्रीनटेक मेगा फूड पार्क लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय गुप्ता ने मेगा फूड पार्क के माध्यम से खाद्यान के उचित उपयोग को रेखांकित किया। नाबार्ड-उदयपुर के डीडीएम शशिकमल ने नाबार्ड द्वारा पोषित विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी दी। पैट्रिक श्लाटर तथा ईव्स सूट्स ने अपने स्टार्ट-अप का परिचय देते हुए उनकी सेवाओं में किये नवाचार के बारे में जानकारी दी।